ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-8* September- 2017
Innovation The Research Concept

वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का योगदान

रामसुरेन्द्र यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
राजकीय पी0 जी0 कालेज,
मुसाफिरखाना अमेठी

सारांश

वित्तीय समावेशन समावेशी, सन्तुलित एवं धारणीय विकास के लिए एक आधारभूत स्तम्भ है। निम्न आय एवं बैंकिंग क्षेत्र से उपेक्षित वर्ग के लोगों को बैकिंग सुविधा वहनीय लागत पर उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के उन लोगों को जो अब तक मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें मुख्य आर्थिक धारा से जोड़ना एवं कम से कम लागत की बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराना है। पिछले दो दशकों में बैंकिग क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत से प्रभावी बदलाव देखने को मिले है। जैसे बैंकिंग सुविधाएं, फण्ड हस्तान्तरण, पारा बैंकिग, मोबाइल बैंकिग, ई बैंकिग, डिजिटल पेमेन्ट इत्यादि। शोध पत्र के माध्यम से वित्तीय समावेशन की स्थिति, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो एक अनुसूचित बैंक है, के रूप में योगदान को समझने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वित्तीय समावेशन, पारा बैंकिग, नावार्ड, आर0बी0आई, ई बैंकिग, डिजिटल पेमेन्ट इत्यादि।

प्रस्तावना

वित्तीय समावेशन देश में समावेशी विकास का मुख्य घटक है। इसका प्रमुख उद्देश्य देशभर में समाज के असुरक्षित और कमजोर वर्गो को निवेश के अवसर और आर्थिक वृद्धि का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आसान शर्त्तों पर धन मुहैया कराना है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के उन लोगों को, जो अब तक मूलभूत बैंकिग सुविधाओं से वंचित थे उन्हें देश की मुख्य आर्थिक धारा से जोड़ना एवं कम लागत पर बैकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन के जरिए पूरे देश में समान रूप से विकसित और बेहतर सामाजिक विकास सम्भव होता है। इसका लक्ष्य जमा और भुगतान खाता, साख बीमा और पेंशन जैसे व्यापक वित्तीय सेवाओं को वृहद स्तर पर सुलभ कराना है।

चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक वृहद हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है जिसका विकास हुए बिना भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर सन्तुलित होकर नही चल सकती है। अतः ग्रामीण विकास होना एक प्रमुख अनिवार्य शर्त है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोई भी व्यवसायी या उद्यमी छोटा या बड़ा जिसको एक व्यवसाय या उद्योग को चलाने के लिए उसके अपने साधन सीमित होते है अतः ऐसी जरुरी साधन को पूर्ण करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं का मजबूत होना जरूरी है। इस प्रकार ऐसी जरुरत को पूर्ण करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मील का पत्थर साबित हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र है। वित्तीय समावेशन योजना को ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी अंचलों में सफल बनाने हेतु उसने उल्लेखनीय कार्य किया है।

अतः वित्तीय समावेशन का मुख्य लक्ष्य, बैकिंग सेवाओं के माध्यम से देश के अधिक से अधिक नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और आय का उचित प्रबन्ध करना है।

वित्तीय समावेशन के अर्न्तगत, बैंक खाता, बचत, बीमा, भुगतान एवं धन का प्रेषण, वित्तीय सलाह इत्यादि सेवाओं में वृद्धि कर उसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती लागतों पर उपलब्ध कराना है। जैसा कि विदित है कि, वर्ष 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन की जांच करने के लिए खान आयोग का गठन किया । इस आयोग की सिफारिस के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वाणिज्यिक बैंको को एक मूलभूत नो फ्रिल बैंक खाता बनाने की अपील की। भारत में अधिकारिक रूप से वित्तीय समावेशन को एक बैंकिग नीति के रूप में वर्ष 2005 में के0सी0 चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट के बाद अमल में लाना शुरू किया गया। इसके बाद बैंको ने निचले स्तर पर रहने

वाले लोगों को ध्यान में रखकर बैंक खाता खोलने की शर्तो को आसान करने की प्रक्रिया शुरू की।

साहित्य समीक्षा

प्रो0 राव बाला अप्पा एवं राव जी रामजी भीम (2016) ने अपने शोधपत्र 'रिजनल रूरल बैंक एण्ड फाइनेन्सियल इनक्लुजन' में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं वित्तीय समावेशन का अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी वृहद पहुंच स्थिति स्थापित की है। यह बैंक कृषि कार्य, हथकरघा उद्योग एवं प्राथमिक क्षेत्र को ऋण एवं साख सुविधा प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, यह बैंक प्राथमिक क्षेत्रों को अपनी कुल अग्रिम साख का लगभग 80 प्रतिशत साख के रूप में उपलब्ध कराता है। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र के गृहस्थ एवं किसानों के लघु जमाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्य से जरूरतमन्द गृहस्थ एवं किसानों को साख की सुविधा प्रदान करता है।

अन्ततः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण अंचलों में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवथा के विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसे समस्त कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से यह बैंक ग्रामीण लोगों को वित्तीय साक्षरता की सेवा भी प्रदान करता है और उनके लिए अपने यहां बैंक खाता खोलता है तथा उपरोक्त सभी वित्त सेवाएं उनके खाते के माध्यम से प्रदान करता है।

गौरव लोधा एवं आई0 वी0 त्रिवेदी (2015) (ए फाइनेन्सियल इनक्लूजन थ्रो रिजनल रूरल बैंक्स) वर्ष 2013 एवं 2014 के आधार पर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि भारत के ग्रामीण विकास एवं वित्तीय समावेशन के प्रसार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समाज के पिछड़े वर्ग, ग्रामीण निर्धन एवं कम आय वाले लोगों की सेवा करता है। इस अध्ययन में वित्तीय समावेशन में बैंक के योगदान का अध्ययन ग्रामीण, अर्धशहरी एवं शहरी आधार पर किया गया, जिसमें यह पाया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय समावेशन में सार्थक भूमिका है।

बेग (2014)(द रोल ऑफ रिजनल रूरल बैंक्स इन फाइनेन्सियल इनक्लूजनः ऐन इम्पीरिकल स्टडी इन इन्डिया) वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका का अध्ययन किया गया। इस विश्लेषण में यह पाया गया कि बैंकिंग क्षेत्र से उपेक्षित ग्रामीण निर्धन लोगों को व्यापक बैंकिंग सेवाएं सुनिस्चित कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सोनी एवं कापरे (2012)(ए स्टडी आन करेन्ट स्टेट्स आफ रिजनल रूरल बैंक इन इन्डिया) इसके अन्तर्गत वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक की अवधि के दौरान बैंकों, शाखाओं, ऋण एवं अग्रिम आदि की संख्याओं के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन मूल्यांकन का विश्लेषण किया गया, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रदर्शन धनात्मक पाया गया।

जय (1996)(परफारमेन्स आफ रिजनल रूरल बैंक्स इन इन्डिया): विश्लेषण में पाया गया कि वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण उधारकर्ताओं को ऋण वितरण के लिए अधिक कुशल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को और अधिक कुशल बनाने के लिए स्थानीय भागीदारी, ऋण की उचित निगरानी और शहरी शाखाएं खोलने जैसे आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता ?

वित्तीय समावेशन की नीति बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा कृषि कार्य में संलग्न है और कृषि वर्ग को तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जैसे ऊँची ब्याज दर, कृषि क्षेत्र में भारी अनिश्चितता, इस क्षेत्र में बीमा कवर का अभाव, लगातार बढ़ती लागत, महाजनी सूद का लगातार मजबूत होता शिंकजा आदि। इन समस्याओं के चलते यह वर्ग बैंकिग क्षेत्र से उसी तरह से दुराग्रह पालने लगता है, जैसे महाजनों तथा अन्य सूद खोर प्रवृत्ति के लोगों के प्रति उसने पाला था। इसलिए यह आवश्यकता है कि वित्तीय क्षेत्र विशेषकर बैकिंग के प्रति इस वर्ग के दुराग्रहों को दूर किया जाए। इसलिए वित्तीय समावेशन की नीति के तहत निचले तथा अभी तक वित्तीय क्षेत्र के प्रति उपेक्षा करने वालों को वित्तीय धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया।

शोध प्रविधि

यह शोध पत्र विवरणात्मक प्रकृति का है जो वित्तीय समावेशन के तथ्यों पर प्रकाश डालता है तथा वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के योगदान का मूल्यांकन करता है। इस शोध पत्र में प्रस्तुत की गयी सूचनायें द्वितीयक आकड़ों के रूप में प्रयोग किये गये हैं, जिसमें विभिन्न शोध पत्र–पत्रिकाएं, नाबार्ड एवं आर बी0 आई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों इत्यादि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन विस्तार का अध्ययन करना।
2. भारतीय वित्तीय प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के महत्त्वपूर्ण योगदान का अध्ययन करना।

महत्त्व

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को बैकिंग सेवाओं एवं वित्तीय सुविधाओं का लाभ कम से कम लागत पर प्रदान करना है। अतः इस अध्ययन के द्वारा समग्र वित्तीय समावेशन का अध्ययन एवं उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के योगदान का अध्ययन करना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु अपनाएं गए मॉडल/प्रतिमान

मूलभूत नो फ्रिल खाते खोलना

नो फ्रिल खाते जिन्हें वर्तमान में जन धन खाते के नाम से जाना जाता है, को खोलने की सलाह दी गई। रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2008), के सिफारिशों के आधार पर गरीबों को जमा, साख, व्यक्ति बीमा और धन

की सुरक्षित वापसी आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक के विस्तार पर बल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पायलट परियोजना के तौर पर बैंकों को कम से कम किसी एक जिले की पहचान करने का सुझाव दिया गया जहां 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

नो योर कस्टमर को आसान बनाना

बैकिंग प्रणाली द्वारा अपने ग्राहकों के बारे में जानने की प्रक्रिया को आसान बनाना भी इस प्रक्रिया द्वारा उठाया गया समझदारी भरा कदम है।

बी0सी0 मॉडल

बैकिंग कॉरेस्पोंडेंट माडल इंटरनेट पर आधारित व्यवस्था है जिसे कोई अधिकृत व्यक्ति लैपटाप या कम्प्यूटर से संचालित कर सकता है। यह एक कार्ड रहित प्रणाली है जिसमें ग्राहक आपना खाता संख्या एवं आधार संख्या का सहायता से लेन–देन कर सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा किसानों को कृषि कार्यों के लिए एक निश्चित सीमा तक ऋण (कृषि साख) प्रदान किया जाता है।

सामान्य क्रेडिट कार्ड

(GCC) इस योजना के अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को नकदी प्रवाह के आधार पर बिना प्रतिभूति, ऋण के उद्देश्य या उसके अन्तिम प्रयोजन की बाध्यता के निर्बाध ऋण उपलब्ध करवाना है। इसके अन्तर्गत अधिकतम ऋण की राशि रु0 25000/–है तथा यह सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को नहीं दी जाएगी। यह सुविधा नो फ्रील 'खाता धारकों को भी मिलेगी।

मोबाइल वैन

मोबाइल ए0टी0एम0 वैन रुपे डेविट कार्ड के उपयोग प्रदर्शन हेतु विशिष्ट रुप से निर्मित है। वैन का वाह्य स्वरूप बैंक के प्रचार एवं रुपे डेविट कार्ड की जानकारी से अच्छादित है। इस प्रकार से यह ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार का भी एक साधन है। वैन में लगा कम्प्यूटर बैंक की कोर बैंकिंग सर्विस कनेक्टिविटी सुविधा से जुड़ा हुआ होताा है।

वित्तीय साक्षरता

ग्रामीण में वित्तीय साक्षरता की ललक जगाने के लिए बैंक उन्हें विभिन्न बैकिंग सुविधायें एवं उनके लाभ के विषय में जागरूक करने का कार्य करते हैं। वित्तीय साक्षरता केन्द्र का संचालन बैंक के सेवा निवृत्त कर्मचारी करते है जिन्हें कान्उसलर कहते है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

यह योजना वित्तीय समावेशन की ओर से निहितार्थ केवल बैकिंग सुविधा प्रदान करने से कहीं आगे है। चूंकि आर्थिक विकास के लिए वृहद बैकिंग क्षेत्र के निर्माण और प्रसार की आवश्यकता होती है। यह योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का सम्मिलित रुप है। अतः ऐसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बैक खाता का होना आवश्यक है जो वित्तीय समावेशन का प्राथमिक आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन की स्थिति का अवलोकन

वित्तीय समावेशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसका उद्देश्य समाज के एक बड़े समूह को जो कि आर्थिक रुप से कमजोर, पिछड़ा एवं बैकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं से वंचित है, को बैकिंग सुविधाएं एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। निम्नलिखित आँकड़ों से वित्तीय समावेशन की स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है।

तालिका–1

बैकिंग सेवाओं युक्त–घरों की स्थिति

	2001 की जनगणना के आधार पर			2011 की जनगणना के आधार पर		
गृह	गृहों/घरों की संख्या	बैकिंग सेवायुक्त घरों की संख्या	प्रतिशत	गृहों/घरों की संख्या	बैकिंग सेवायुक्त घरों की संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	138271559	41639949	30%	167826730	91369805	54.4%
शहरी	53692376	26590693	49.5%	78865937	53444983	67.8%
कुल	**191963935**	**68230642**	**35.5%**	**246692667**	**144814788**	**58.7%**

स्रोत–रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (वित्तीय समावेशन की स्थिति का अवलोकन)

तालिका–2(1)

वित्तीय समावेशन प्रगति–बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

मद	2011	2012	2013	2014	2015
गाँवों में बैकिंग स्रोत					
(क) शाखा	33378	34811	37471	40837	46126
(ख) शाखा विहीन मोड	34316	81397	144282	227617	337678
कुल	**67694**	**116208**	**181753**	**268454**	**383804**
बैकिंग कॉरेस्पोंडेन्ट वाले शहरी क्षेत्र	447	3771	5891	27143	60730

तालिका–2(2)

आधारभूत बचत जमा खाता शाखा

मद	2011	2012	2013	2014	2015
(क) संख्या 10 लाख में	60.19	73.13	81.20	100.80	126.00
(ख) राशि 10 लाख में	44.33	57.89	109.87	164.69	273.30

तालिका–2(3)

आधारभूत बचत बैक जमा खाता (बैकिंग कारेस्पोंडेन्ट)

मद	2011	2012	2013	2014	2015
(क) संख्या 10 लाख में	13.27	31.63	57.30	81.27	116.90
(ख) राशि 10 लाख में	10.69	18.23	10.54	18.22	36.00

तालिका–2(4)

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति

मद	2011	2012	2013	2014	2015
(क) संख्या 10 लाख में	21.31	27.11	30.24	33.79	39.90
(ख) राशि 10 लाख में	1240.10	1600.05	2068.39	2623.00	3684.50

तालिका–2(5)

साधारण क्रेडिट कार्ड (GCC)की स्थिति

मद	2011	2012	2013	2014	2015
(क) संख्या 10 लाख में	1.40	1.70	2.11	3.60	7.40
(ख) राशि 10 लाख में	35.10	35.07	41.84	76.30	1096.90

स्रोत–भारत सरकार (2014सी), आर0बी0आई0 (2013, 2014, 2015) (योजना पत्रिका में प्रकाशित)

व्याख्या

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन की स्थिति में अनुकरणीय प्रगति हुई है। गॉवों में बैकिंग स्रोत के अन्तर्गत शाखा वर्ष 2011, में जहां 33378 थी वही 2015 में 46126 हो गई है तथा बी0सी0 मॉडल वाले शहरी क्षेत्र में जहां 2011 में 447 शहरी क्षेत्र जुड़े थे वही वर्ष 2015 में 60730 शहरी क्षेत्र इस सुविधा से जुड़ चुके है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा जहां वर्ष 2011 में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 21.31% थी वही 2015 में 39.90% तक यह सुविधा प्रदान की गयी है। साधारण क्रेडिट कार्ड की सुविधा में भी अनुकरणीय वृद्धि दर्ज की गयी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय समावेशन में योगदान

निम्न आय एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों को बैकिंग सुविधाएं वहनीय लागत पर उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन है। इस योजना को ग्रामीण परिवेश में, जहां आरक्षित, आर्थिक रुप से कमजोर, समाज के निचले तबके के लोग जिन्हें बैकिंग व्यवहार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक इकाई के रुप में प्रशंसनीय कार्य किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने इस योजना को सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहा है। कार्य क्षेत्र एवं संख्या की परिधि से बाहर निकलकर वित्तीय समावेशन योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है–

तालिका–3

बैंक समूह एवं जन संख्या समूह के आधार पर श्रेणी वार कार्यरत बैंक शाखाओं की संख्या की स्थिति (31 मार्च 2015)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगर	कुल
स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं उसके सहायक	8.029	6593	4304	3622	22548
राष्ट्रीयकृत बैंक	21228	16428	12604	11325	61585
अन्य सार्वधनिक क्षेत्र के बैंक	377	528	479	378	1762
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	**14613**	**3747**	**1071**	**228**	**19660**
निजी बैंक	4302	6457	4521	4698	19978
विदेशी बैंक	8	12	57	247	324
सकल कुल	**48557**	**33766**	**23036**	**20498**	**125857**

स्रोत–भारतीय रिजर्व बैक की वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय समावेशन पर आधारित)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट हो रहा है कि वित्तीय समावेशन योजना को पूर्ण करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का चौथा स्थान है, कुल शाखाओं का लगभग 16% हिस्सा ग्रामीण बैक द्वारा पूर्ण किया जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका तीसरा स्थान बैक शाखा के रुप में देखा जा सकता है।

तालिका–4
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत खोले गये खातों की स्थिति (15.07.2015 तक)

विवरण	खातों की संख्या			आंकडे (करोड में) (%)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	रूपये डेविट कार्ड खातों की संख्या	खाते में शेष रु0	अन्य शेष खाते का प्रतिशत
सार्वधनिक क्षेत्र के बैंक	7.24	5.98	13.22	12.25	15698.68	50.83
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	**2.57**	**0.44**	**3.02**	**2.19**	**3493.76**	**50.00**
निजी बैंक	0.41	0.28	0.69	0.61	1095.93	47.83
कुल	**10.22**	**6.70**	**16.93**	**15.05**	**20288.37**	**148.66**

स्रोत–डी0एफ0एस0 (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया) (जी0ओ0आई0)

व्याख्या

प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ मूलभूत बैकिंग सुविधा एवं सेवाओं को सीधे बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाता है जिसके लिए बैंक खाते का होना अति आवश्यक है। इस तालिका से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका अन्य दो क्षेत्र के बैंकों के लगभग बराबर है तथा खातों की संख्या के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का प्रदर्शन संतोषजनक स्थिति में है। शून्य शेष के आधार पर कुल खोले गये खातों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य दो बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं निजी बैंक के प्रतिशत के रुप में बराबर का योगदान है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रुप से, वित्तीय समावेशन योजना समाज के प्रत्येक वर्ग को बैकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया एक सार्थक प्रयास है। हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता होने से सरकार द्वारा प्रदान की गई, हस्तान्तरण आय, सब्सिडी इत्यादि मौद्रिक लाभ को समय पर सीधे खाते में भेज दी जाएगी। बैकिंग क्षेत्र का विस्तार होगा, बाजार में तरलता बनी रहेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, ग्रामीण स्तर पर वित्तीय समावेशन योजना को सफल बनाने में सार्थक प्रयास कर रहा है। इस योजना से क्षेत्रीय ग्रामीण बैक में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा बैकिंग प्रणाली और अधिक मजबूत होगी।

संदर्भ सूची

1. *प्रो0 राव बाला अप्पा एवं राव जी रामजी भीम (2016) 'रिजनल रूरल बैंक एण्ड फाइनेन्शियल इनक्लुजन': विद्यानिकेतन जर्नल आफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, वालूम न0 4 (1) जून 2016 पेज 46–63*
2. *गौरव लोधा एवं आई0 वी0 त्रिवेदी (2015) 'ए फाइनेन्शियल इनक्लूजन थ्रो रिजनल रूरल बैंक्स': इन्टरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च इन बिजनेस मैनेजमेंट वालूम 3, ईसु 10,नवम्बर 2015, पेज 77–82*
3. *अर्चना, एच0 एन0, अगस्त (2013) फाइनेन्शियल इनक्लूजन– रोल आफ इन्स्टीट्च्यूशन आई0 जे0 बी0 एम0, 44–48.*
4. *बारी, बलवन्त कुमार, जुलाई (2017), रोल आफ रीजनल रूरल बैंक इन फाइनेन्शियल इन्क्लूज़नः एडिटेड बुक, फाइनेन्शियल इनक्लुजन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पेज 200–218, भारती पब्लिकेशन, नयी दिल्ली।*
5. *योजना अगस्त (2015) इनक्लेसिव ग्रोथ एण्ड सोसल चेन्जेज आई0एस0एस0एन0–0971–8397.पेज 10–11*
6. *www.rbi.org.in*
7. *www.nabarfd.org.in*